14.43 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*Contd.*

DECLARATION OF REPUBLIC BY RHODESIAN GOVERNMENT—*contd.*

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं दुवारा लोक महत्व के निम्न लिखित विषय की ओर वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"रोडेशिया की सरकार द्वारा गणतंत्र की घोषणा और उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया"

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : I shall read the statement again.

The Prime Minister has already stated the stand of the Government of India on the recent development in Rhodesia in the course of her reply to the debate in this House on the 4th of March on the President's Address to the joint session of Parliament. Honourable Members are aware that we withdrew our Mission from Salisbury six months before the Unilateral Declaration of Independence and have had no connections with the illegal regime. We have steadfastly supported the U.N. sanctions and have repeatedly called upon the Government of U.K., as the administering power, to take all measures including the use of force, to establish majority rule in Rhodesia.

We consider the act of the racist regime to declare itself a Republic as totally illegal. We hope that it will not be recognised by any civilised nation in the world. We also hope that all the States which continue to maintain diplomatic, consular, economic or military connections with Rhodesia will immediately sever their connections with it. In this connection, we are happy to note that some Governments which had representation in Rhodesia such as U.S.A., France, F. R. G., Italy, Netherlands and Norway have decided to withdraw their Consulates from Salisbury.

We are convinced that the illegal regime would not have survived if all the members of the U.N. had strictly observed the general and mandatory sanctions adopted by the Security Council. Keeping in view the fact that these sanctions have not succeeded so far, we believe that full support to the UN resolutions by all member States including the use of force by UK is the only way to establish the legitimate rights of the peopl e of Zimbabwe.

In line with our policy on this subject, we shall continue to support any proposals that may be put forth in the U.N. and outside for establishing majority rule in Zimbabwe on the basis of one man one vote.

I am sure the House will join me in conveying our tribute, sympathy and support to the petriots of Zimbabwe in their just struggle against the illegal racist regime of Salisburry for their inalienable right to freedom.

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। जो भावना मंत्री महोदय की है वही भावना सारे सदन की है और सारे देश की है।

रोडेशिया की सरकार ने गणतंत्र की घोषणा की और ऐसा करके स्मिथ सरकार ने सारी दुनिया की राय को डिफाई किया है। जैसा मंत्री महोदय ने कहा है यह सही है कि दुनिया के देश युनाइटिड नहीं हैं।

अपनी भावनाओं को लोग ईमानदारी से व्यक्त नहीं करते हैं, केवल दिखाने के लिए ही करते है। अन्दर उनके मन में कुछ और होता है। सिक्योरिटी काउन्सिल ने जो इकोनोमिक सेंकशंज लगाई थीं, वे भी सफल नहीं हुई। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यू. एस. फ्रांस, स्विटजरलैण्ड आदि देश भी पुर्तगाल और अफ्रीका के जरिये से रोडेशिया के साथ ट्रेड कर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन सेंकशंज के

[श्री कंवरलाल गुप्त]

बाद रोडेशिया की आर्थिक अवस्था बिगड़ी नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा सुधर गई है। वहां रेट आफ ग्रोथ दस परसेंट हो गया है। और पिछले साल उनकी एक्सपोर्ट तीस परसेंट ज्यादा हो गई। गणतंत्र की घोषणा करके स्मिथ सरकार ने हमेशा के लिए वहां व्हाइट सुप्रेमेसी की स्थापना कर दी है। मैजोरिटी रूल का जो सिद्धांत है, इस प्रकार से रेशल डिसक्रिमिनेशन करके उन्होंने उस सिद्धान्त की अवहेलना की है, उस हक को लोगों से छीना है। जो विधान उन्होंने बनाया है उसमें 66 लेजिस्लेटर होंगे जिनमें से 50 गोरे होंगे और जिनकी तादाद चार गुना है, उनकी संख्या केवल 16 होगी। उन्होंने दो जोन बनाये हैं, एक ब्लैक जोन और एक व्हाइट जोन। इस प्रकार से रंग के आधार पर डिसक्रिमिनेशन करना मनुष्यता के खिलाफ है।

मैं सवाल करता हूं। आपने कहा है कि यू. के. की सरकार को अपने लिखा था कि वह फोर्स इस्तेमाल करे। यू. के. की सरकार ने उसका क्या जवाब दिया है? यु. के. की सरकार अगर ईमानदार है तो क्यों फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहती है?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या भारत सरकार अफ्रीका और एशिया के देशों की कान्फ्रेंस बुलाएगी जिसमें इस मामले को उठा कर रोडेशिया सरकार को बाध्य किया जाए कि वह इस गणतंत्र की घोषणा को वापिस लेकर बहुमत की आवाज के सामने झुके।

आपने रोडेशिया के मामले में यह बात मानी है कि एक आदमी और एक वोट। लेकिन दूसरे देशों में जहां इस बात को नहीं माना गया है, उनको भी आप कंडेम करेंगे? फिजी में भारतियों की संख्या काफी है। वहां पर भी एक आदमी के पीछे एक वोट नहीं है। जो रोडेशिया में हो रहा है वह वहां भी कुछ मात्रा में हो रहा है। यह जो सिद्धान्त है यह सब देशों में एप्लाई हो, केवल रोडेशिया में नही, क्या आप इसका समर्थन करेंगे और इसको सभी जगह लागू कराने की कोशिश करेंगे।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सारे देश की भावनाओं को व्यक्त करते हुए रोडेशिया सरकार की इस कार्यवाही को कनडेम करें, ताकि सारा संसार इस देश की भावनाओं से अवगत हो।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इसमें कोई शुबहा नहीं है कि जो कुछ रोडेशिया ने किया है, उसको कनडेम करने में हिन्दुस्तान पीछे नहीं है। यह सरकार और तमाम मुल्क उसको कनडेम करता है। माननीय सदस्य ने सवाल पूछने से पहले रोडेशिया की हालत के बारे में जो कुछ कहा है, मैं उसमें पूरी तरह सहमत हूं। यह शर्म की बात है कि इस जमाने में रोडेशिया सारी दुनिया की राय की परवाह न करते हुए अपनी नीति पर चलता रहे और किसी की बात को न माने।

हमने यू० के० को कई मर्तबा रोडेशिया में मैजारिटी रूल स्थापित करने के लिए फोर्स इस्तेमाल करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं हमने सिक्यूरिटी कौंसिल और जेनेरल एसेम्बली के उन रेजोल्यूशन्ज को सपोर्ट किया है, जिनमें ब्रिटेन से कहा गया है कि अगर वह इस मामले को बगैर फोर्स के इस्तेमाल के हल नहीं कर सकता है, तो वह फोर्स इस्तेमाल करे। लेकिन ब्रिटेन की तरफ से बार-बार यह जवाब मिलता है कि हम फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके पीछे क्या वजह है, हमारे लिये यह कहना मुश्किल है। लेकिन ब्रिटेन साफ कहता है कि वह फोर्स इस्तेमाल नहीं करेगा। उसका कहना है कि रोडेशिया पर जो सैंक्शन्ज इम्पोज की गई है, अगर वे चार, पांच, छः साल तक चलती रहें, तो उनका असर जरूर होगा और रोडेशिया के रेसिस्ट रेजीम को मजबूर होकर वर्ल्ड ओपीनियन के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटेन की तरफ से यह बात कहे जाने के बावजूद सैंक्शन्ज कामयाब नहीं हुई हैं। यह फैक्ट है कि दो चार मुल्क ऐसे हैं, जो रोडेशिया से को-आपरेट कर रहे हैं, जिनकी मार्फत उसको सामान पहुंच

रहा है और बाहार जा रहा है । मैं समझता का कुछ मार्जिनल इफेक्ट हुआ होगा, लेकिन वे न होने के बराबर हैं ।

हमारी समस्या यह है कि हम इससे ज्यादा क्या करें । जब यू० एन० में इस पर बहस हुई, तो हमने उस प्रस्ताव को सपोर्ट किया । जहां जहां और जब जब मौका मिला है, हमने रोडेशिया की कार्यवाही को कनडेम किया है । लेकिन दिक्कत यह है कि इस सिलसिले में कोई कामयाबी नहीं हो रही है । हम क्या करें ।

माननीय सदस्य ने कहा है कि हम इस बारे में एफ्रो- एशियन कन्ट्रीज की एक कांफ्रेंस काल करें । यह सुझाव अच्छा है, लेकिन इस की खास जरूरत इस लिए नहीं है कि यह मामला यू० एन० ओ० के सामने आ चुका है, जो कि संसार की एक बडी संस्था है, जिसमें सब देश रिप्रेजेन्टेड है । एफ्रो-एशियन कन्ट्रीज की आर्गनाइजेशन ने इस बारे में एक रेजोल्यूशन पास करके रोडेशिया को कनडेम किया है और हमने उसको सपोर्ट किया है । और किसी कांफ्रेंस को बुलाने से यह मसला हल नहीं होगा । जब भी कोई मौका आयेगा, हम रोडेशिया की जनता के अधिकारों का समर्थन करेंगे ।

जहां तक वन-मैन-वन वोट के उसूल का ताल्लुक है, हम उसके कायल है और हम चाहते है कि वह हर जगह एप्लाई किया जाय ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी): रोडेशिया में 50 लाख लोगों में से 2,20 हजार श्वेत लोगों ने जो अपनी तथा-कथित रिपब्लिक का एलान किया है, वह सारें मानव-समाज के लिए एक चुनौती है । हमारे देश के आजाद होने से पहले भी इस तरह के मसले सामने आये थे और उन दिनों भी हम ने उनको हल करने में अपना पूरा योगदान किया था । आप जानते हैं कि स्पेन में फ्रैंको के खिलाफ रिपब्लिकन्ज की लड़ाई हुई थी । उस समय हिन्दुस्तान में एक स्पेन कमेटी बनी थी, जिस के सेक्रेटरी डा० राम मनोहर लोहिया थे । वह कमेटी रिपब्लिकन्ज की मदद के लिये चन्दा इकटठा करती थी और अन्य साधन जुटाती थी । बाहर श्री कृष्ण मेनन उस धन और सहायता को यथा-स्थान पहुंचाते थे । उसके बाद जब एबीसीनिया पर मसोलीनी का हमला हुआ और जुल्म हुए, वो हिन्दुस्तान ने उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द की । ब्रसेल्ज की कांफ्रेंस में साम्राज्यवाद के जुल्म के खिलाफ लडने के लिये एक परम्परा शुरू की गई थी ।

रोडेशिया की समस्या के सम्बन्ध में दो रास्ते है । मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में कहा है :

> "I am sure the House will join me in conveying our tribute, sympathy and support to the patriots of Zimbabwe in their just struggle against the illegal racist regime of Salisbury for their inalienable right to freedom."

जब वे लोग अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे है, तो हमारा यह फर्ज हो जाता है कि हम अपनी पुरानी परम्परा के मुताबिक उन की मदद करें । इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में उनके समर्थन में आवाज बुलन्द की जाय और उसके माध्यम से कोई रास्ता निकाला जाये । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार रोडेशिया के एक्सप्लायटिड कलर्ड लोगों की सहायता के लिए, वहां के उन फ्रीडम फाइटर्ज को मदद देने के लिए, एडटु रोडेशिया पीपल नाम की कोई कमेटी बनायेगी–श्री श्रीकृष्णमेनन हमारे बीच में मौजूद है, उनके मातहत ही सही जो हिन्दुस्तान के कोने कोने से चन्दा और अन्य मदद इकटठी करे और रोडेशिया के फ्रीडम फाइटर्ज के साथ सम्बन्ध जोड़ कर उनको वह मदद पहुंचाए ?

मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि यू. एन. ओ. में रोडेशिया के विरुद्ध जिन

[श्री शिव चन्द झा]
मैन्डेटरी सेक्शन्ज को लागू करने का प्रस्ताव पास किया गया है, बहुत से राष्ट्रों ने उनको लागू नहीं किया है और इसी लिए यह परिस्थिति पैदा हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत के रिप्रेजेन्टेटिव्ज ने कितनी दफा यू. एन. ओ. में यह प्रश्न उठाया कि तमाम राष्ट्र उन मैन्डेटरी सैक्शन्ज को मुस्तैदी के साथ लागू नहीं कर रहे हैं।

यह ठीक है कि इंग्लैण्ड इस सम्बन्ध में फोर्स का रास्ता अख्त्यार नहीं करना चाहता है और नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे सामने कई नजीरें हैं कि कई अवसरों पर युनाइटिड नेशन्ज ने पुलिस एक्शन लिया। क्या सरकार युनाटिड नेशन्ज में यह मूव करेगी कि यदि ब्रिटेन फोर्स इस्तेमाल नहीं करता है, तो युनाइटिड नेशन्ज रोडेशियां के खिलाफ पुलिस एक्शन ले ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जहां तक रोडेशिया के फ्रीडम फाइटर्ज की मदद करने या उनके पक्ष में आवाज उठाने का सवाल है, मैंने पहले ही कहा है कि जब जब यू. एन. ओ. या सिक्यूरिटी कौन्सिल में या और जगह यह मसला सामने आया है और इस पर बहस हुई है, तब हमारे नुमायदों ने बुलन्द आवाज से रोडेशिया के लोगों के राइट्स को सपोर्ट किया है और रोडेशिया की सरकार को कनडेम किया है।

रोडशिया के जो फ्रीडम फाइटर्ज आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और बड़ी बहादुरी के साथ बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, उन्होंने जब भी कोई मदद मांगी है, वह हमने दी है। हमने उसके लिए मेडिसन्ज, कपड़े और जीपें दी हैं। हमने पहले भी उनकी मदद की है और जब उनकी तरफ से कोई और मांग आयेगी, तो हम उनको पूरी मदद देंगे।

श्री शिव चन्द्र झा : यह तो मानवता की बात हैं। हिन्दुस्तान की परस्परा हमेशा आजादी के लिए संघर्ष करने वालों की मदद करने की रही हैं। सरकार इस विषय में क्या कर रही है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हम उन परस्पराओं को कायम रख रहे हैं और उन लोगों को इमदाद दे रहे हैं।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : माननीय सदस्य ने राडेशिया की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वालों की सहायता देने के लिए एक कमेटी बनाने और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पुलिस एक्शन लिये जाने का प्रश्न उठाया है। क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जहां तक पुलिस एक्शन का सवाल है, जब यू. एन. के सामने यह मसला आयेगा, तो वह अपने आप तय करेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है ?

श्री रामसेवक यादव : भारत सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जब यह सवाल उठेगा तो भारत सरकार अपनी राय देगी।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : क्या भारत-सरकार पहलकदमी करके यू. एन. में यह सवाल उठायेगी और रोडेशिया के खिलाफ पुलिस एक्शन लिये जाने का प्रस्ताव पेश करेगी।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस वक्त हमारा यह ख्याल नहीं है। लेकिन हम इसके बारे में गौर कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

15 hrs.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी भी देश को आजाद करते हुए आज तक की परंपरा के अनुसार ऐसा कभी नहीं किया कि उसने इंडिपेंडेंट कांस्टीटयूशन मेजारिटी के आधार पर पास करके, तब आजादी दी लेकिन राडेशिया के लिए कभी बिटिश गवर्नमेंट ने आजादी देने से पहले यह रियायत दी कि वह बहुमत का राज्य कि जब जी में आए बना ले। इस प्रकार उन मुट्ठीभर गोरे लोगों को अधिकार दे दिया जिससे कि वह आज राज्य करते रहें। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इग्लैंड

की जनता बिलकुल नहीं चाहती कि रोडेशिया में काले लोगों का राज भ्रा जाय। वह वहां गोरों का ही राज चाहते है। अन्दर की बात तो यह यह है भ्रौर उन्होंने इसी कारण से शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी जगह किया यहां नहीं किया। और जो आर्थिक प्रतिबन्ध उन्होंने लगाया हैं, उसकी जांच के लिये सात कामनवेल्थ देशों की कमेटी है उसका भारत भी सदस्य है उसकी रिपोर्ट है कि 440 लाख पौंड का सामान टू बैंको भ्रादि स्विजरलैंड और पांर्चुगीज देशों के द्वारा होता हुआ अमेरिका पश्चिमी जर्मनी व जापान में पहुंचा, इन सब देशों में माल भ्राया। मैं यह बात बताना चाहता हूं कि भ्रमेरिका भ्रौर इंग्लैंड नहीं चाहते कि वहां गोरों का प्रभूत्व हटे भ्रौर वन मैंन वन वोट के भ्राधार पर वहां कालों को अधिकार मिले। स्मिथ के शब्दों में कोई छिपी हुई बात नहीं है स्मिथ, ने यह बात कही है कि "रोडेशिया विल रिमेन इन कि सिविलाइज्ड हैंडस्"। यह सभ्य लोगों के हाथ में ही रहेगा। काले लोगों को वह सभ्य मानते ही नहीं है। गोरों को सभ्य मानते है, यह उनकी घोषित नीति है।

भ्रब मैं इस भ्राधार पर प्रश्न करना चाहता हूं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि गवर्नमेंट ने इसमें भ्रपनी कुछ नीति चेंज की है। जब कभी काश्मीर का या भ्रौर कोई प्रश्न भ्राता है तो गवर्नमेंट की घोषित नीति रही है कि सभी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक और भ्रहिंसात्मक उपायों से होना चाहिये। मैं धन्यवाद देता हूं कि भ्रापने उसमें आज परिवर्तन किया है भ्रौर आपने यह कहा है....(**व्यवधान**).....

तो मेरा पहला प्रश्न यही है कि क्या आप यह अनुभव करते है कि व्यापारिक प्रतिबन्ध असफल हो चुके हैं भ्रौर भारत सरकार की दृष्टि में रोडेशिया को, वहां की जनता को, काले लोगों को सही स्वतंत्रता दिलाने के लिए अब कौनसा मार्ग शेष रह गया है. यह मैं जानना चाहूंगा।

दूसरे, आपने यह जो कहा है कि शक्ति इस्तेमाल करें, तो इंग्लैंड ने मना कर दिया है, यू० एन का कोई रेजोल्यूशन नहीं है, तो मैं आपसे साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं कि आपने जो कहा है कि अगर आउट-साइड भी रोडेशिया की आजादी के लिए कोई प्रयत्न होगा तो आप उसमें सहायता करेंगे, तो रोडेशिया के चारों तरफ टंजानिया आदि क्षेत्रों में इस प्रकार की जो लिबरेशन आर्मी बनाई गई हैं कि जो राडेशिया को आजादी दिलाने के लिए प्रयत्नशील है, तो क्या आप उनके सशस्त्र संघर्ष में सहयोग देंगे भ्रर्थात पैसे से और सेना से क्या भ्राप सहायता देने के लिए तैयार है या केवल आप शाब्दिक सहयोग देंगे ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जहां तक कि सैंक्संस का सवाल है मैं पहले भी कह चुका हूं कि सैंक्शंस कामयाब नहीं हो रहे है और यह भी सही है कि बहुत से मुल्क ऐसे हे जिन्होंने वादा किया था कि सैंक्शंस को इम्पोंज करेंगे वह उनसे ट्रेड कर रहे है और वह जो आपने फीगर्स मेंशन की हैं 44 मिलियन का सामान भेजा है वह भी सही है भ्रौर यह बड़े दुख की बात है और शर्म की बात है कि जो मुल्क वादा करते है वह उस वादे को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए उसमें नाकामयाबी होती है ..... (**व्यवधान**) ..... सवाल जहां तक हमारे करने का है हम तो उनके साथ है, भ्रफ्रीकन मुल्को के साथ है ......

श्री ओमप्रकाश त्यागी : मैंने पूछा था कि आपकी गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से राडेशिया को आजादी दिलाने के लिये अब कौनसा मार्ग शेष रहता है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : सबसे पहले तो हमारे ख्याल से इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी यू के की है..

श्री ओमप्रकाश त्यागी : उसने मना कर दिया है।

श्री सुरेन्द्र पालसिंह : मना करते रहें, वह बात दूसरी है। लेकिन जिम्मेदारी उनकी है।

श्री ओमप्रकाश त्यागी : ब्रिटेन मनाकर चुका है, ऐसी अवस्था में आपका क्या सुझाव है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैंने शुरू में यह अर्ज किया कि पहली जिम्मेदारी यू के की है, ऐडमिनिस्टरिंग एथारिटि वह हैं, वह जो कुछ भी करें उनका फर्ज होता है कि उनको आकर हटाएं चाहे जरिए उनको कुछ भी इस्तेमाल करने पड़ें अगर वह नहीं कर पाते हैं तो मामला उठाने का जहां तक सवाल है, सेक्योरिटी कौंसिल में और यू एन असेम्बली में, वह रास्ता भी अख्त्यार किया जा चुका है। आपको मालूम है कि 65 से लेकर आज तक पांच छै रेजाल्यूशन हो चुके हैं, सब बात कही जा चुकी है उसमें नाकामयाबी हो रही है। रोडेशिया नहीं मान रहा हैं उस बात को। अब यह चीज ऐसी है इसमें तो सभी अफ्रीकन कंट्रीज से कंसल्ट करने का सवाल है कि क्या करना है। हम इतना ही कह सकते हैं कि जो वह करेंगे उसमें हम सहयोग देंगे। हम तो हमेशा यही इन्सिस्ट कर रहे हैं कि यू के को आगे आना चाहिए. इस समय तो हम उन्हीं के ऊपर जोर डाले कि वह करे। उसके लिए जो कुछ वह तय करेंगे. उनके साथ हम रहेंगे।

श्री ओमप्रकाश त्यागी : जवाब नहीं दिया। मेरे दूसरे भाग का जवाब दीजिए, टंजानिया आदि मे जो लिबरेशन आर्मी बन रही है रोडेशिया को आजाद करने के लिए उस सशस्त्र संघर्ष में आप उसे धन से और सेना से अपनी मदद करेंगे या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं पहले भी कह चुका हूं कि जहां तक फ्रीडम फाइटर्स के आर्गेनाइजेशन का सवाल है वह जो भी हमसे इमदाद मांगेंगे वह सहायता हम दे रहे हैं और देंगे।

श्री ओमप्रकाश त्यागी : सेना की सहायता ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : सेना की सहायता का सवाल नहीं उठता।

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi) : About Rhodesia, the first requirement is to know the map of Africa. I wonder whether the Prime Minisetr, the Foreign Minister or the distinguished Minister present here is even remotely familiar with the map of Africa, because when they make their tour itineraries, it is Europe, the USA and elsewhere that their eyes are turned to rather than to the continent of Africa.

On the East of Rhodesia, we have Mozambique; on the west, we have Angola and on the south, South Africa and on the north helpless Zambia.

The reply of the hon. Minister focussed only on Rhodesia as if is to be considered in a vacuum. If any serious effort has to be made for the liberation of the people of this territory, it is imperative that we consider what will happen to Angola and Mozambique. But this does not suit our British friends who regard Portugal as their most ancient ally. It is not on the cards of the two conservative powers—I call them both conservative, the United States and the Soviet Union; it is also not a strategy for China which is keeping Macao, because Macao is used for gold trade with South Africa by China. So, all these three big powers are developing an outlook which encourages the present pattern of power distribution in this part of the world. And what are the stark facts of of military power? I wish the hon. Minister had been honest and he had told us about this, because this House has a right to be informed of the facts. It is no use deluding this House with polite answers drafted in the Ministry of External Affairs. Today, Rhodesia has terrific air power, and it has a military agreement to co-ordinate its air power with that of the Union of South Africa. So, here you have in the continent of Africa a monstrous possibility of aerial bembardment of the Africans by these two powers, namely Rhodesia and South Africa. That is what the future has in store. And what spectacle do we present here in this House? The Prime Minister does not bother to come. The Minister is probably outside somewhere.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member should come to his question now.

SHRI M. L. SONDHI : But these things are taken note of by the rest of the world. Bear with me, Sir, for a minute. You have borne with so much today and I congratulate you on your patence. The question which I would like to ask is this. Are Government going to have a consistent attitude at different times or not? When the questlon of the Commonwealth was being discussed here, they came to the House and said that we were in the Commonwealth because we wanted to safeguard the future of the Africans in Rhodesia. Now, you have failed to safeguard the future of theAfricans in Rhodesia, because Rhodasia has been declared a Republic. Are you coming to the House as honest men, saying 'We will now' quite the Commonwealth here and now? Are you doing it ?

Government are acquiescing in the policies of the major powers and snapping the ties which bind this House, and the Indian people with the freedom struggle. My specific and pointed question to the Minister would be this. Are they giving any evidence that they are helping the Africans? Here in Delhi, we have the spectacle of Mr. Alford Nazole, the cheif representative of the African National Congress, who pines away; that poor unfortunate person appeals to them, but they follow the example of Lord Nelson and put the telescope to the blind eye. This is what has happened to the distinguished representative of the South African National Congress right here in New Delhi, in my constituency..

MR. DEPUTY-SPEAKER : We are with Rhodesia.

SHRI M. L. SONDHI : We can spend so many hours in trading complements. On this issue of Rhodesia, has the hon. Minister the honesty, the simple requirement of honesty and is he prepared to tell us that in Anglo and Mozambique, the Government of India have a policy to be adopted and which is to be announced here and now?

All the time they have been taking shelter behind the state secrecy, and yet their secrets are available anywhere. They are traded on the market every day. Can't he give us an honest answer about Angola and Mozambique ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : We are on Rhodesia and not Angola or Mozambique.

SHRI M. L. SONDHI : Sir, may I congratulate you because you represent the aspirations of the younger Members of the House. You know these are all matters on which this House should rise above the ordinary level, If we mean something for the people in Rhodesia, we have to tackle this question Otherwise, what will happen? They are landlords; you cannot do anything. His good wisher are not going to reach there. Does he have a policy, a co-ordinated policy, about Angola and Mozambique and Rhodesia and also in respect of that country. Zambia, that poor, unfortunate country which is being pressurised? Let the answer, therefore, be in terms of specific criteria and especially with reference to air power. No amount of resolutions in the United Nations will prevail upon the Rhodesians from using the terrible air power, napalm-bombs and all those agents of destruction by which the African people will be killed.

Could you let us remember what Tagore once had spoken in anguish, when he pledged the support of the Indian people to the African people? Is this Minister here to tell us that he does not care a hang for all those sacred pledges. Let his reply be honest, straightforward and let him disclose also his knowledge about Africa.

SHRI SURENDRA PAL SINGH : Mr. Duputy- Speaker, Sir, I am grateful [to the hon. Member for having onlighetened me about the geography of Africa. I have got this elementary knowledge; I know exactly how Rhodesia is placed *vis a vis* Mozambique and south Africa. I myself have said that it is the non-co-operation of these two countries which is causing trouble, because they are also governed by such Resist regimes. These two countries are fully co-operating with Rhodesia and that is the main stumbling-block. Whatever, we want to do in that area in regard to sanctions, etc., it is completely nullified by this help which these two countries are giving by

[Shri Surendra Pal Singh]

the back door to Rhodesia. But the difficulty is, what can we do?

SHRI M. L. SONDHI : Act,(*Interruption*)

SHRI SURENDRA PAL SINGH: How?

SHRI M. L. SONDHI : If you cannot, resign; we will do.

SHRI SURENDRA PAL SINGH: Whatever can be done, we are doing. I have already said we are one with the rest of the world in this matter. Whatever the matter is being discussed, whatever they want to do, we are in full support. Now, what more can we do ? (*Interruption*)

As regards helping the freedom-fighters, I have already said that whatever has or been asked for, we have been giving it to them. Whatever is decided taken up by the African countries themselves or by the wold community, we are with them. We will support all their actions and their resolutions in this regard, I do not see what else we can do. I sympathise with them. I respact the hon. Member's sentiment about it, but mere expression of sentiment will not do. (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Papers to be laid on the Table.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, before yon take up the next item, you will also condemn this. The whole House is concerned about it. It is a major problem.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Bring a motion before the House.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : You had better express your sympathy.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, no. The whole House can do it in the proper way.

15.13 har.

PAPERS LAID ON THE TABLE

REPORTS OF LAW COMMISSION

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) : On be half of Shri Govind Menon, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers:—

(1) (i) Thirty-third Report of the Law Commission on section 44 of the Code of Criminal Procedure, 1898.

(ii) Thirty-sixth Report of the Law Commission on sections 497, 498 and 499 of the Code of Criminal Procedure, 1898-grant of bail with conditions.

(iii) Thirty-seventh Report of the Law Commission on the Code of Criminal Procedure, 1898, section 1 to 176.

(iv) Thirty-ninth Report of the Law Commission on the punishment of imprisenment for life under the Indian Penal Code.

(v) Forty-first Report of the Law Commission on the Code of Criminal Procedure, 1898-Vols. and 2.

(2) A statement showing reasons for delay in laying the above Reports. [*Pleaced in Library. See No. LT-2810/70*]

NOTIFICATION UNDER ESSENTIAL COMMODITIES ACT, AND-REPORTS OF AGRO INDUSTRIES CORPORATION, LTD. BUNGLORE AND LUCKNOW

SHRI SHER SINGH : On behalf of Shri Annasahib Shinde I beg to lay on the Table:—

(1) A copy of the sugar (Price Determination) Order, 1970 (Hindi and English versions) published in Notification No, G.S.R. 265 in Gazette of India dated the 20th February, 1970, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [*Pleaced in Library. See No. LT — 2811/70*]